THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) and (b). Modernisation of the organisational structure, training arrangements, weapons and equipment, etc., of the Armed Forces is a continuous process and is undertaken from time to time in the light of Defence needs, the development, in our general security environment, scientific and technological advances made, and as part of essential replacement and replenishment programmes. We have been able to achieve some progress in this behalf and further steps are in hand. The Annual Report and the Budget proposals laid before the House indicate some details. For reasons which will, no doubt, be appreciated, it would not be in the public interest to disclose further details.

विद्युत परियोजना के लिये महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता

600. **श्री हरी शंकर महाले** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने किन-किन विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मांग की है और ऐसी परियोजनाओं के लिए कितनी राशि की मांग की गई है ;

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इन परियोजनाओं के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० राममूर्ति) : (क) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य में गैसटर्बाइन यूनिटों की प्रतिष्ठापना के वित्त पोषण के लिए, राज्य की योजना से बाहर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाय । सेटों का आयात करने संबंधी टेंडरों को तथा अन्य शर्तों को अन्तिम रूप न देने के बाद ही, विदेशी मुद्रा तथा रुपयों दोनों ही रूप में परियोजना की लागत निश्चित रूप से जानी जा सकेगी। कितनी सहायता की आवश्यकता है उसकी मात्रा सुनिश्चित तौर पर नहीं बतायी गई है परन्तु रुपयों के रूप में होने वाले व्यय को तथा विदेशी मुद्रा की लागतों को पूरा करने के लिये ऋण दिए जाने के संबंध में प्रार्थना की गई है ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार/बिजली बोर्ड के अनुरोध के संबंध में सरकार की राय का अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । तथापि, सामान्यत: सभी विद्युत परियोजनाओं को धन राज्य की योजना से दिया जाता है जिसके लिए भारत सरकार द्वारा एकमुश्त केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

(ग) गैस टर्बाइनों के लिए महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने अभी आर्डर नहीं दिए हैं । उन्होंने, ईंधन की उपलब्धता के आधार पर, 60-60 मेगावाट की 2 यूनिटों की प्रतिष्ठापन संबंधी अपने पहले के प्रस्ताव को हाल ही में संशोधित करके चार यूनिटों का प्रस्ताव किया है ।